VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1523)

Name of Candidate	AAKIP KHAN		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	256964
Center	Jaipur	Date	25/12/2020

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Enumerate the issues associated with functioning of the Central Information Commission. How can these issues be addressed?

(150 words) 10

केंद्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली से संबद्ध मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। इन मुद्दों का कैसे समाधान किया जा सकता है?

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, सूचना का अधिकार अधिनियम-(RTI)-2005 के तहत एक विधिक आयोग के रूप मे हुआ है जिसका उद्देश्य सूचना के अधिकार को वास्तविक रूप देना है।

केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से संबद्ध मुद्दे:-

- पिछले 5 वर्षों मे अधिकांश समय मे केन्द्र मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली रहा है, जो इसकी कार्यप्रणाली को रोकता है।
- इस आयोग मे सूचना आयुक्तो की कमी रहती है
- सूचना से संबंधी शिकायतो का निवारण प्रभावी नही होता
- समय पर सूचना नही दी जाती
- विभिन्न क्षेत्रो मे PIO नियुक्त नही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सरकारी कानून जैसे अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम - 1923, जो इस कानून से संघर्ष करते नजर आते है
- सरकारी हस्तक्षेप व राजनीतिक अतिक्रमण, जो इसकी विश्वसनीयता और प्रभावकारिता को प्रभावित करते है

समाधान

- पर्याप्त सूचना आयुक्त व PIOs की नियुक्ति
- नियुक्ति निष्पक्ष रूप से होना, इसके लिए नियुक्ति समीति प्रभावी व निष्पक्ष हो
- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र हो
- सूचना सक्रियताओ (व्यक्तियो) की सुरक्षा का प्रावधान हो
- सभी सार्वजनिक पहलूओ से संबंध रखने वाली सूचनाओ को इस अधिनियम के तहत लाया जाए

सूचना का अधिकार, हमारे लोकतंत्र मे एक क्रांतिकारि बदलाव को इंगित करता है जिसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. In India, Governor's discretionary powers are wider than those of the President. Elaborate. (150 words) 10

भारत में, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए।

भारत मे लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमे संवैधानिक प्रमुख रूप मे केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रपति व राज्य स्तर पर राज्यपाल का प्रावधान है

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति	राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति
संविधान मे राष्ट्रपति के लिए किसी प्रकार की विवेकाधीन शक्ति का प्रावधान नही है	जबकी राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 163 मे प्रावधान है
राष्ट्रपति को केवल परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त है	अनुसूची-6 के तहत आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों मे विवेकाधीन शक्तियाँ
(जब माननीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए जब केन्द्र मे कोई भी दल बहुमत साबित	अनुच्छेद 200 व 201 के तहत राष्ट्रपति को आरक्षित रखने के लिए विधेयक की राज्यपाल की शक्तियाँ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

करने की स्थिति मे न हो

- जब कोई भी दल सरकार बनाने के लिए आगे न आए तो इन परिस्थितियों मे राष्ट्रपति अपने संज्ञान से निर्णय ले सकता है।

- अनुच्छेद 365 के तहत संवैधानिक विफलता की स्थिति मे राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की शक्तियाँ
- अनुसूची-5 के तहत राष्ट्रपति के निर्देशों पर कार्य करने की शक्ति
- अन्य क्षेत्रों मे एक प्रशासक के तौर पर कार्य करने पर शक्तियाँ जैसे संघशासित प्रदेशों मे
- राज्य सरकार को बहुमत साबित करने की निर्देश देने की शक्ति

परिस्थिति जन्य

- जब मुख्यमंत्री मर जाए
- जब कोई भी दल बहुमत मे न हो
- आदि, तो सरकार बनाने की शक्ति

इस प्रकार राष्ट्रपति व राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की हमारी संवैधानिक प्रकृति के कारण विभिन्नता मिलती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Highlight the objectives that were sought to be achieved through tribunals. How successful have they been in meeting them? (150 words) 10

उन उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए जिन्हें अधिकरणों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। वे उन्हें पूर्ण करने में कितने सफल रहे हैं?

अधिकरण, अधिकांशतः अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएं होती है, जिनका गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए या क्षेत्र लिए न्यायिक प्रणाली स्थापित करने हेतु किया जाता है।

अधिकरणों से प्राप्त करने के लिए उद्देश्य =>

- न्याय प्रणाली में जटिलता को कम करना व इसे सरल व तीव्र बनाना।
- भारतीय न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ को कम करना।
- आधुनिक समाज के विकास के अनुरूप कुछ क्षेत्रकों के तकनीकी विकास व न्याय प्रणाली में समन्वयता लाना।
- साथ ही न्यायिक के साथ-साथ कार्यकारी पक्षों को भी रेखांकित करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्राप्त करने में सफलता

सफलताऐं

- पर्यावरणीय न्याय तीव्र हुआ है, NGT के गठन के कारण
- NCLAT व NCLT जैसे अधिकरणों के गठन से, कॉर्पोरेट शासन में सुधार हुआ है
- साथ ही देश में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को CCI के गठन से बढ़ावा मिला है
- कुछ नदी अधिकरण भी सफल रहे हैं, जैसे कृष्णा नदी अधिकरण
- सशस्त्र बलों में न्याय सशस्त्र अधिकरणों से

विफलताऐं

- सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद-136 की शक्तियाँ होने के कारण, अंत में मामला न्यायालय में चला ही जाता है।
- नदीय अधिकरण अधिकांशतः असफल रहे हैं (कावेरी, महानदी आदि)
- साथ ही इन अधिकरणों में कार्यकारी के अवांछित हस्तक्षेप भी रहा है।
- साथ ही देश में न्यायिक बोझ अभी भी अत्यधिक है [3cr मामले]

न्यायाधिकरणों की सफलता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2010 के निर्णय के क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Instead of the government regulating Over-the-top (OTT) platforms, there have been calls for a self-regulating mechanism for such platforms, as in the case of print media. Discuss. **(150 words) 10**

सरकार द्वारा ओवर-द-टॉप (ओ.टी.टी.) प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के स्थान पर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्व-विनियमन तंत्र हेतु आह्वान किया गया है, जैसे कि प्रिंट मीडिया के मामले में किया गया है। चर्चा कीजिए।

ओवर-द-टॉप प्लेटफार्म ऐसे प्लेटफार्म होते है, जो वीडियो ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल से वहत कार्य करते है, जैसे नेटफ्लिक्स आदि।

O.T.T. प्लेटफॉर्म के स्वनियमन पर बल →

- सरकार के विनियमन से इन प्लेटफार्म का नवाचार व नवोन्मेष रुकता है
- साथ ही सरकारी विनियमन, इनके वैश्विक जुड़ाव को भी प्रभावित करता है
- साथ ही यह [पसंद के आधार] पर चलने वाले प्लेटफार्म है, इसलिए यह किसी के विकल्प चुनने के अधिकार का भी हनन नहीं करते
- इन प्लेटफार्मो पर अत्यधिक जनसंख्या को रोजगार भी मिलता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

* साथ ही इन प्लेटफार्मो की स्वायत्ता व निष्पक्षता भी प्रभावित होती है।

हालांकी कुछ मुद्दे भी नजर आते है जो निम्न है।

* इन प्लेटफार्मों पर बाल-पार्नोग्राफी आदि जैसी अश्लील सामग्री का खतरा रहता है
* साथ ही इन प्लेटफार्मों पर कट्टरवाद आदि का भी प्रसार हो सकता है
* महिला शोषण को बढ़ावा मिलता है
* इनकी [जवाबदेही] तय नही होती

हाल ही मे सरकार द्वारा इन्हे सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया गया है, आवश्यकता है की एक संतुलित मॉडल को अपनाकर इनको प्रोत्साहित किया जाए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Bring out the arguments surrounding the issue of some states reserving jobs for locals in the private sector. **(150 words) 10**

कुछ राज्यों द्वारा निजी क्षेत्रक में नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित मुद्दे के चतुर्दिक तर्कों को स्पष्ट कीजिए।

हाल ही हरियाणा, mp, कर्नाटक आदि जैसे राज्यो द्वारा नौकरियो को स्थानीय लोगो को आरक्षित करने हेतु प्रावधान किये गये।

निजी क्षेत्रक मे नौकरियो को आरक्षित करने से संबंधित मुद्दे

- संविधान के (अनुच्छेद-14—18) (समानता का अधिकार) के विरुद्ध नजर आते है
- संविधान के अनुसार निवास की शर्त केवल संसद लगा सकती है, न की राज्य इसलिए यह संवैधानिक रूप से भी प्रश्न चिह्नित है
- इससे (निवेश रुकता) है क्योंकी निजी क्षेत्रक को बाधा नजर आती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* साथ ही [स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा] पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है,

* निजी क्षेत्रक को [कुशल श्रमिक] भी नहीं मिलते

* साथ ही यह कुछ प्रतिशत लोगों को ही रोजगार प्रदान कर सकता है, इसलिए यह बेरोजगारी का भी समाधान नहीं है।

उपरोक्त मुद्दे इस प्रकरण की समस्याओं को उजागर करते है। राज्यों को आवश्यकता है की वह कौशल विकास, अवसंरचना निर्माण व अन्य संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान देकर राज्य का विकास करें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Identifying the key elements of Mission Karmayogi, briefly explain how it can lead to holistic development of the human resources and state's capacity. **(150 words) 10**

मिशन कर्मयोगी के प्रमुख तत्वों की पहचान करते हुए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि इससे मानव संसाधन और राज्य की क्षमता का समग्र विकास कैसे हो सकता है।

मिशन कर्मयोगी हाल ही मे सरकार द्वारा लोकसेवाओ की कार्यप्रणाली व संरचनात्मक मुद्दो को संबोधित करने के लिए लाया गया

परिक्षण

- राष्ट्रीय डेशबोर्ड द्वारा ... निगरानी
- कर्मीयो की वार्षिक रिपोर्ट
- विभाग/संगठन/प्रगति रिपोर्ट द्वारा निगरानी व समन्वय

मिशन कर्मयोगी → प्रशिक्षण कार्यक्रम

- I-GOT कर्मयोगी प्लेटफार्म द्वारा CSPV बनाएगी
- इस पर नये कौशल पाठ्यक्रम होंगे
- लोकसेवक हार्ड कौशल व सोफ्ट कौशल प्राप्त कर सकेगे

प्रधानमंत्री मानव संसाधन आयोग → समन्वय समूह → मानव संसाधन आयोग

कार्य:

- प्रशिक्षण मानको मे एकरूपता लाना
- पारस्परिक मानव संसाधन का विकास — विभागो मे कर्मीयो के कौशल मे एकरूपता
- अंकेक्षण मानको को बनाए — नये प्रशिक्षण मानक लाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मानव संसाधन का विकास

- शेयर (पारस्परिक) मानव संसाधन से आवश्यकतानुसार कर्मीयो की नियुक्ति
- लोकसेवको मे विशेषज्ञ ज्ञान को आत्मसातीकरण
- साथ ही उच्च प्रशिक्षण मानक
- मानव संसाधन के वार्षिक प्रगति की निगरानी

राज्य की क्षमता का समग्र विकास

- लोक सेवको के प्रतिबद्ध व कुशल होने से संसाधनो का सदुपयोग होगा
- लोकसेवको के तत्पर, संवेदनशील होने से लोक सेवा वितरण दक्ष होगा
- लोक सेवको मे सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा होने से भ्रष्टाचार कम होगा

मिशन कर्मयोगी

देश मे लोकसेवाओ के कायाकल्प को पलटने की क्षमता रखता है इसको वास्तविक क्रियान्वयन होना चाहिए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Highlighting the role played by ASHA workers in public health system of India, discuss the challenges faced by them. (150 words) 10

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करते हुए, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

आशा कार्यकर्ताओ की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के तहत की जाति है, जो की एक साक्षर स्थानीय महिला होति है।

आशा कार्यकर्ताओ की भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मे भूमिका

- जनसंख्या नियोजन, जिससे परिवार विकास संभव हुआ है व महिला स्वास्थ्य भी
- आवश्यक सेवाओ का वितरण, जैसे गर्भ निरोधक, पोषण युक्त खाद्य आदि
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे प्रमुख सहायक व कार्यकर्ता के रूप मे
- कोविड -19 के दौरान संक्रमित क्षेत्रो की पहचान व देखभाल मे
- महिलाओ को घर पर स्वास्थ्य सुविधाऐ प्रदान करने मे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

* पेशे संबंधी हीनता, क्योंकी लोग इसे हीन कार्य समझते है
* कम वेतन, जो इनकी आजीविका के लिए भी पूर्ण नहीं है
* कोई समाजिक सुरक्षा नहीं, जिसले इनकी आजीविका असुरक्षित रहती है।
* अधिकांशतः निम्न जातियो से संबंधित होने के कारण सामुदायिक सहयोग भी नहीं मिलता।
* साथ ही आवश्यक प्रशिक्षण व पेशेवरो का अभाव

आशा कार्यकर्तायो के लिए आवश्यक वेतन, समाजिक सुरक्षा तय करने की आवश्यकता है, इसके लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य नीति लाई जा सकती है, और इसे संस्थागत रूप दिया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While internationalisation of higher education has many potential benefits for India, certain challenges will need to be addressed in this regard. Discuss. (150 words) 10

यद्यपि उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के भारत के लिए कई संभावित लाभ हैं, तथापि इस संबंध में कुछ चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए।

हाल ही मे बजट - 2020 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 मे उच्चतर शिक्षा के अंतराष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रावधान किये गये।

भारत के लिए लाभ

- देश मे अनुसंधान व विकास बढ़ सकेगा
- भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानो मे तकनीक आ सकेगी
- भारत मे आवश्यक विशेषज्ञ प्रोफेसर आ सकेंगे
- अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा।
- साथ ही देश मे शिक्षा क्षेत्र मे निवेश बढ़ेगा।

इस संबंध मे कुछ चुनौतियाँ

- इससे शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ेगा, जो शिक्षा को एक ~~सार्वज~~ सार्वजनिक धर्म से विचलित करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* वंचित वर्गों का इस प्रकार के संस्थानों से अलगाव होगा और वह पिछड़ जायेंगे जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के विरुद्ध है।

* हमारे देश में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों के विनियमन का मुद्दा भी अहम नजर आता है

* साथ ही यह कुछ ही क्षेत्रों पर केन्द्रित हो सकते हैं जिससे अन्य क्षेत्रों से असमानता बढ़ सकती है।

उपरोक्त चुनौतियों के समाधान के लिए कुछ विशिष्ट दिशा-निर्देश व मानदंड तय किये जा सकते हैं, ताकि शिक्षा का विकास व सार्वभौमिक पहुंच दोनों पूर्ण हो सकें।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. India needs to adopt a more pragmatic stance in the context of the ongoing intra-Afghan talks. Discuss, in the light of India's engagement with Afghanistan. **(150 words) 10**

भारत को वर्तमान में जारी अंतरा-अफगान वार्ताओं के संदर्भ में अधिक व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के जुड़ाव के आलोक में चर्चा कीजिए।

~~भारत~~ अफगानिस्तान मे शांति स्थापित करने और स्थाई सरकार बनाने को लेकर चल रही कोशिशो और प्रयासो को अंतरा- अफगान वार्ता की संज्ञा दी गई है।

भारत को व्यवहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता :-

- भारत का लगभग 3 bil $ का निवेश अफगानिस्तान मे है जिसे सुरक्षित रखने के लिए भारत को तालिबान की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है
- चूँकी अब यह लगभग सिद्ध हो चुका है, की तालिबान के शासन मे आने की संभावना है इसलिए भारत की आन्तरिक सुरक्षा (PoK,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कश्मीर आदि) के लिए भारत को तालिबान से वार्ता का रुख अपनाना चाहिए।

* साथ ही विश्व की सभी बड़ी शक्तियाँ (USA, रूस) आज तालिबान से बातचीत कर रही है, इसलिए भारत द्वारा तालिबान से वार्ता न करने का कोई मुद्दा भी नहीं बचता।

* साथ ही यदि भारत व्यवहारिक रुख नहीं अपनाता है तो इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ेगा।

* साथ ही इस क्षेत्र शरणार्थी संकट भी भारत में आ सकता है।

* भारत में तस्करी, संगठित अपराध आदि को रोकने के लिए भी आवश्यक है।

भारत ने हमेशा ही अफगान की चुनी हुई सरकार को महत्व दिया है, लेकिन राष्ट्रहितों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती

10. In the geo-strategic context of West Asia, the recent efforts to normalise relations between Israel and UAE may open new possibilities for India. Analyse. **(150 words) 10**

पश्चिम एशिया के भू-रणनीतिक संदर्भ में, इजरायल और यू.ए.ई. के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों से भारत हेतु नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। विश्लेषण कीजिए।

हाल ही मे इज़राइल व यू-एई के मध्य अब्राहम समझौते के माध्यम से संबंधो को सामान्य बनाया गया, जिससे भारत को निम्न भू-रणनीतिक संभावनाऐ प्राप्त होति है।

- पहले भारत को

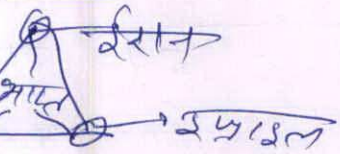

इन तीनो सबसे से संतुलित संबंध बनाने के प्रयास करने पड़ते थे, अब इसकी समस्या नही होगी

- साथ ही इससे इस क्षेत्र मे शांति स्थापित हो सकती है जिससे भारत मे तेल आपूर्ति का संकट भी कम होगा, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है

- साथ ही अब भारत को इज़राइल व खाड़ी देश दोनो पक्षो से रणनीतिक सहयोग, सुरक्षात्मक मुद्दो

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भर प्राप्त हो सकता है

* साथ ही आतंकवाद से निपटने में भी भारत के लिए संभावनाएं बन सकती है

* इसके अलावा भारत में पश्चिमी एशियाई व इज़राइल दोनों पक्षों से निवेश बन सकता है।

* पाकिस्तान के मुद्दे पर भी भारत को इन दोनों पक्षों से सहयोग प्राप्त हो सकता है।

हालांकि कुछ चुनौतियाँ जैसे ईरान के साथ संबंध आदि बन भी सकती है। इसलिए भारत को अपनी कूटनीति में संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. It is not only the content of election manifestos but also the past performance with respect to promises made in election manifestos that need to be regulated. Discuss. **(250 words) 15**

केवल चुनावी घोषणा-पत्रों की विषयवस्तु को ही नहीं, बल्कि चुनावी घोषणा-पत्रों में किए गए वादों से संबंधित विगत निष्पादन को भी विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

चुनावी घोषणा-पत्र, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रक्रिया से पहले अधिक से अधिक मतों को हासिल करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया एक भविष्य नीतिगत वादा होता है।

चुनावी घोषणापत्रों की विषयवस्तु के विनियमन की आवश्यकता -

- चुनावों में धार्मिक मुद्दों पर प्रचार प्रसार को रोकने के लिए
- साथ ही चुनावों में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संयमित करने के लिए
- इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा मतों को लुभाने के लिए किये गये अवांछित वादों रोकने के लिए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* इसके अलावा घोषणापत्र की विषय वस्तु व वास्तविकता में अधिक समीपता लाने के लिए
* घोषणापत्र में बहुलवादी विचारों के प्रभाव को कम करने के लिए व अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए
* विकासात्मक विषय - वस्तु को बढ़ावा देने के लिए

उपरोक्त विषय-वस्तु के साथ-साथ निष्पादन को विनियमित करने की आवश्यकता

* ताकी राजनीतिक दल, किये गये वादों को पूर्ण कर सके या तत्पर हो
* ताकी घोषणापत्रों में अवास्तविक वादे न हो
* साथ ही जनता को घोषणा पत्रों का वास्तविक चेहरा

दिखाने के लिए

- लोकतांत्रिक समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए

- सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही व उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए

- राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिकरण के लिए

- और राजनीतिक मुद्दों में व्यक्तित्व केन्द्रित अभिवृत्ति को मुद्दा केन्द्रित अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए।

चुनावी घोषणापत्र लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का एक प्रमुख माध्यम है, जहाँ जनता की अपेक्षाएं जुड़ी होती है, इसलिए चुनावी घोषणा पत्रों के कायापलट की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. In order to achieve a reduction in the pendency of cases and a return to the Supreme Court's original role as a final appellate court, setting up of a National Court of Appeal is the need of the hour. Discuss. **(250 words) 15**

लंबित वादों की संख्या में कमी लाने और उच्चतम न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में उसकी मूल भूमिका में पुन: स्थापित करने के लिए, एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करना समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

राष्ट्रीय अपील न्यायलय, उच्च न्यायलय और सर्वोच्च न्यायलय के मध्य अपील के विशेषिक उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया। न्यायलय होता है

आवश्यकता

- वर्तमान मे सर्वोच्च न्यायलय मे लगभग 60,000 अपीले लंबित है, जिसका समाधान हो सकता है

- साथ ही उच्चतम न्यायलय संवैधानिक मुद्दो पर अधिक ध्यान दे सकता है, ओपरा सिंघल मामला सिर्फ 2 न्यायधिशो की बेंच द्वारा देखा गया।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- साथ ही उससे अपीलों का निपटान भी तीव्र हो सकता है
- विधि आयोग ने भी सर्वोच्च न्यायलय की शाखाये खोलने की सलाह दी है
- साथ ही उच्चतर न्यायलय सिर्फ एक अंतिम अपीलीय न्यायलय के रूप मे अपनी भूमिका को पुनः स्थापित कर सकता है।

लेकिन उपरोक्त के बावजूद अपील का राष्ट्र न्यायलय के समक्ष निम्न मुद्दे उभर आते है–

- सर्वोच्च न्यायलय को अपनी शीर्षता की शक्तियाँ, अन्य न्यायलय के साथ विभाजित करनी पड़ेगी, जिससे उच्चतर न्यायलय की एक शीर्ष न्यायलय के रूप मे भूमिका कम होगी [अनुच्छेद – 136, 142 etc]

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

साथ ही पहले ही अन्य न्यायालयो मे रिक्तियाँ है, इसलिए इस न्यायालय मे न्यायधीश कैसे लाए जाएँगे।

उपरोक्त मुद्दो व चाओ को देखते हुए, अपील के राष्ट्र न्यायलय को स्थापित करने से पहले पर्याप्त चर्चा की आवश्यकता है, साथ ही वर्तमान न्यायिक प्रणाली मे सुधार की।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The Constitution of India reflects an amalgamation of spirit of Indian freedom struggle and various administrative provisions of different acts of British rule in India. Explain. **(250 words) 15**

भारत का संविधान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की भावना और भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न अधिनियमों के अनेक प्रशासनिक प्रावधानों के मिश्रण को दर्शाता है। व्याख्या कीजिए।

भारत का संविधान एक मिश्रित दस्तावेज है, जिस पर अनेको ऐतिहासिक, समकालीन जैसे मुद्दो की छाप नजर आती है

भारतीय संविधान मे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की भावना :-

- भारतीय संविधान मे मौलिक अधिकारो के प्रावधान (भाग-3), जो नागरिक के लिए मूलभूत अधिकार है और जिसके लिए स्वतंत्रता संग्रामियो द्वारा प्रयास किये गये [नेहरू रिपोर्ट आदि]
- भारतीय संविधान मे राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वो के प्रावधान (भाग-4), जो राज्य का उत्तरदायित्व तय करते है, जिनकी ब्रिटिश शासन के दौरान कमी थी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान, जो नागरिकों पर भारतीय होने पर कर्तव्यों को स्पष्ट करते हैं, जो की भारतीय राष्ट्रवाद से प्रेरित है

- भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति, स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान (350) करने का अधिकार जैसे प्रावधान, जो की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में अल्पसंख्यकों के साथ हुई गतिविधियों का परिणाम है

- आर्थिक प्रावधान, जैसे संसाधनों का समान वितरण, मुफ्त कानून आदि जो की कराची अधिवेशन की छाप को दर्शाते हैं

लेकिन अधिनियमों ने अनेक प्रशासनिक प्रावधानों का मिश्रण

- 1919 के अधिनियम से द्विसदनीय

व्यवस्था को अपनाना

- 1861 के अधिनियम से विभागीय उत्तरदायित्व के प्रावधान अपनाना

- 1935 के अधिनियम से
  - राज्यपाल का पद
  - तीन सूचियाँ (संघ, राज्य, समवर्ती)
  - संसदीय व्यवस्था
  - आदि

  को अपनाना

- आरक्षण के प्रावधान, पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रेरित माने जा सकते हैं (1909, 1919 आदि)

- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम -1947 से वर्तमान शासन व्यवस्था का नया दिखा, प्रभावित है।

इस प्रकार भारतीय संविधान एक मिश्रित दस्तावेज है, जिसमें उपरोक्त के अलावा अन्य देशों के संविधानों की भी छाप है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Mention the key components of the SVAMITVA scheme. Also, highlight its intended benefits and discuss the potential issues in its implementation. **(250 words) 15**

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के प्रमुख अवयवों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसके अपेक्षित लाभों को रेखांकित कीजिए तथा इसके कार्यान्वयन में संभावित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

स्वामित्व योजना हाल ही मे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रो मे भूमी रिकॉर्ड के सुधारो के उद्देश्य से लाई गयी

प्रमुख अवयव

- ग्रामीण क्षेत्रो मे व्यक्तिगत सम्पत्ती संबंधी सभी रिकॉर्ड का दस्तावेज बनाना
- इसके लिए नई तकनीकी जैसे ड्रोन, GIS आदि का उपयोग करना
- सम्पत्ती के स्वामित्व से संबंधित वास्तविक लोगो की पहचान करना
- साथ ही संयुक्त परिवारो की सम्पत्ती को तार्किक रूप से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वामित्व अधिकारो मे विभाजित करना।

- इसके अलावा सम्पत्ती के स्वामित्व संबंधी कानूनो के दुरूपयोग को रोकना।
- पंचायतीराज संस्थाओ के सहयोग से पहचान प्रणाली दृढ़ करना।

(लाभ)

- इससे सम्पत्ती के वास्तविक स्वामियो का पता चल सकेगा।
- साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओ के बोगस लाभार्थियो को पहचाना जा सकेगा।
- महिलाओ को सम्पत्ती स्वामित्व मिल सकेगा।
- काले-धन का निवेश रोका जा सकेगा।
- ऐसी भूमियाँ जिन पर सरकार का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होगा है; और अवैधानिक अतिक्रमण की पहचान हो सकेगी
- नीतियों अधिक तार्किक व डेटा के अनुरूप बन सकेगी

सामंजस्य मे मुद्दे

- हमारे देश मे लगभग 6 लाख गाँव है, इसके लिए बड़े स्तर पर पेशेवरों, व तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी
- साथ ही पंचायतीराज संस्थाएं अभी सुदृढ़ नही है, इसलिए सहयोग की अपेक्षा कम हो सकती है
- इसके अलावा **वित्त** की आवश्यकता
- **सामुदायिक सहयोग** का मुद्दा
- जटिल पारिवारिक संरचना, जिससे पहचान करना कठिन कार्य

उपरोक्त कदम एक सराहनीय कदम है, इसके लिए व्यापक नीतिगत सुधारो की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Sharing of information among all stakeholders in government functioning is a leading practice towards good governance. Discuss with examples.

(250 words) 15

सरकारी कार्यप्रणाली में सभी हितधारकों के मध्य सूचना को साझा करना सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परिपाटी है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

सुशासन ऐसे शासन को इंगित करता है, जिसमे शासन व्यवस्था भागीदारीपूर्ण रवैये से जवाबदेह, पारदर्शी व उत्तरदायी हो।

सुशासन के लिए सूचना को साझा करने का महत्व है

- सूचना साझा करने से आम जन की शासन मे भागीदारी बनती है, जो सुशासन का प्रमुख अंग है। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम
- इससे सरकारी कार्यप्रणाली मे पारदर्शिता बढ़ती है, जैसे नागरिक चार्टर से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- साथ ही सरकारी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह व उत्तरदायी बनती है, जैसे सेवोत्तम मॉडल से

- साथ ही सरकारी कर्मियों की सेवा वितरण के प्रति प्रतिबद्धता भी बढ़ती है। जैसे IAS प्रशांत नायर द्वारा शोसल मीडिया के उपयोग मे देखा गया

- साथ ही यह, ईमानदार सरकारी कर्मियों के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत होता है।

- इससे सार्वजनिक संसाधनों का सदुपयोग होता है और सार्वजनिक शुभ की प्राप्ति होति है

- सरकारी कार्यप्रणाली मे लाल फीताशाही कम होति है और

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

शासन सरल व सुगम बनता है।
- अनिवर्तित बदलाव यानि अफसरशाही तंत्र की मनोभावना, सेवाभावना में परिवर्तित होती है
- नागरिक समाज सक्रिय होता है जिससे भ्रष्टाचार कम होता है जैसे 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम विवाद आदि।
- साथ ही इससे शासन में लोकतांत्रिक बदलाव आते हैं, जैसे लोकायुक्त अधिनियम।
- चुनावी सुधार होते हैं जैसे ADR की याचिका पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को हटाना।

इस प्रकार सुशासन व सूचना साझा करना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके लिए ARC-II की सिफारिशें लागू की जानी चाहिए

16. India has an oversized and bloated government which acts as a drag on economic efficiency and growth. Critically evaluate. **(250 words) 15**

भारत में आवश्यकता से अधिक आकार और अतिशय दायित्वों को वहन करने वाली सरकार है, जो आर्थिक दक्षता एवं वृद्धि के संबंध में एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

भारत मै लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली है जिससे सरकार के आकार व दायित्व दोनो प्रभावित होते है

आकार

- लगभग 50 मंत्रालय है

कारण

- गठबंधन की सरकारे
- अल्पसंख्यको की आवश्यकताये
- विशेष क्षेत्रो पर ध्यान → महिला/बाल
- उभरते नये मुद्दे तकनीक (AI, ML)
- आदि

दायित्व

- पिछड़े वर्गो का विकास (महिला, बाल, निम्न जाति)
- आर्थिक वृद्धी
- स्वास्थ्य सुधार
- खाद्य सुरक्षा
- भौतिक सुरक्षा
- बाह्य सुरक्षा
- अंतरिक्ष कार्य
- कृषि सुधार
- शिक्षा आदि

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आर्थिक दक्षता एवं वृद्धी के संबंध में अवरोध ⇒

- अनेको मंत्रालयो से समन्वय करता है और दक्षता प्रभावित होति है [ऊर्जा → ऊर्जा मंत्रालय, नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग]
- साथ ही कुछ मंत्रालय बहुत पुराने व अप्रसांगिक हो गये है
- इसके अलावा इससे प्रशासनिक जटिलता बढती है, जिससे निवेश रूकता है
- इससे लाल फीताशाही बढती है, जो सेवा वितरण को अप्रभावी बनाता है
- इससे संसाधनो का फिजूल खर्च बढता है।
- साथ ही विशेष क्षेत्रको पर ध्यान नही दिया जाता है। जैसे तकनीक पर आदि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी नजर आते है

* वर्तमान गठबंधन के दौर मे मंत्रालय को कम करना, राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है

* साथ ही, अलग मंत्रालय होने से विशेष क्षेत्र मे, विशेषज्ञता बढती है, जैसे कृषि, पर्यावरण मे

* हमारे देश के इतने बडे आकार व जनसंख्या के लिए अधिक व्यापक सरकार और दायित्व होना कोई आश्चर्य नही है।

इसलिए समाधान के रूप मे तकनीकी मिशन भिन्न-भिन्न क्षेत्रो के लिए चलाये जा सकते है, जैसे आयोगो का गठन जो शासन प्रणाली मे सुधार ला सकते है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Though the National Digital Health Mission is a step in the right direction for both patients and the healthcare system, concerns around data privacy need to be addressed. Examine. **(250 words) 15**

यद्यपि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, दोनों के लिए उचित दिशा में उठाया गया एक कदम है, तथापि डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए।

हाल ही मे राष्ट्र डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, देश मे स्वास्थ्य के डिजिटल स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए चतापख्याना प्रस्तावित किया गया

अवयव
- डिजि डॉक्टर
- स्वास्थ्य पहचान पत्र
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड
- व्यक्तिगत चिकित्सा रिकॉर्ड
- गेटवे
- स्वास्थ्य समाधान प्रणाली

रोगियों व स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए लाभ

- इससे रोगियों के पिछले चिकित्सा रिकॉर्डों का पता लगाकर स्वास्थ्य मे सुधार किया जा सकता है
- साथ ही टेलि मेडिसिन से आगामी डॉक्टर दिशा-निर्देश प्राप्त

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किये जा सकते है

- डॉक्टर की पहचान, डिजि डॉक्टर के माध्यम से भी जा सकती है
- साथ ही व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड से, उचित परामर्श दिया जा सकता है
- इसके अलावा स्वास्थ्य पहचान पत्र, डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र मे पहचान प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है

इससे जुड़ी चिंताऐ

- इससे व्यक्तियो का स्वास्थ्य डेटा, डिजिटल मोड मे उपस्थित होगा, जिससे चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है
- डेटा के दुरुपयोग की भी संभावना, जैसे कुछ विशेष वर्गो को लक्षित करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- डेटा के दुरुपयोग से गोपनीयता व निजता के अधिकार के हनन की संभावना
- इससे महिलाओं का शोषण उनके स्वास्थ्य सूचना के डेटा आधार पर दबाव डालकर किया जा सकता है

उपरोक्त चिंताओं के समाधान के लिए ~~बैठे~~ मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति व डेटा संरक्षण विधेयक को पास करने की आवश्यकता है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. One Nation One Ration card has the potential to significantly transform the lives of migrant workers in India. Analyse. **(250 words) 15**

वन नेशन वन राशन कार्ड में भारत में प्रवासी श्रमिकों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से रूपांतरित करने की क्षमता है। विश्लेषण कीजिए।

वन नेशन - वन राशन कार्ड योजना, हमारे देश मे एकीकृत खाद्य वितरण प्रणाली के उद्देश्य से लाई गई थी

इस योजना से प्रवासी श्रमिको को लाभ

- इससे प्रवासी श्रमिक भी खाद्य वितरण प्रणाली का लाभ अन्य राज्यो मे ले सकेगे जिससे वह अभी तक वंचित थे
- साथ ही उनकी एक ही उचित मूल्य की दुकान (FPS) पर निर्भरता घटेगी व बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी
- साथ ही प्रवासीयो को, अन्य राज्यो मे, अपनी आय का एक भाग खाद्य आवश्यकताओ

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी

- साथ ही अन्य राज्यों में भी उन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी
- प्रवासी श्रमिको के पोषण स्वास्थ्य व पोषण सुरक्षा मे भी सुधार होगा।
- उपरोक्त लाभ परिणाम स्वरूप प्रवासी श्रमिको को एक मानव-पूंजी मे परिवर्तित करेगी जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आय बढ़ेगी।

लेकिन उपरोक्त लाभो की संभावना इस योजना के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, जिसमे निम्न चुनौतियाँ है:-

- यह निर्धारित करना कठिन कार्य

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

है क्योंकि किस राज्य मे कितने खाद्यान्नो की आवश्यकता है, क्योंकि प्रवासी श्रमिको की संख्या का पता लगाना कठिन है

- इसके लिए सभी राज्यो मे सहमति व समन्वय का होना पूर्व शर्त है, जो की एक कठिन कार्य है।

- इसके लिए पूरे देश की उचित मूल्य की दुकानो का जुड़ा होना आवश्यक है जो भी एक चुनौति है

- साथ ही FPS की संख्या कम है (5,35000, गॉव → 6 लाख)

- आधार लिंक अनिवार्यता से, वास्तविक लाभार्थी बाहर हो सकते है।

उपरोक्त चुनौतियो के समाधान की आवश्यकता है इसके लिए कम्प्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण आदि को बढ़ावा दिया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The World Trade Organization is buffeted by multiple challenges which have eroded the credibility of the organization. Analyse. **(250 words) 15**
विश्व व्यापार संगठन कई चुनौतियों से ग्रस्त है, जिसने संगठन की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। विश्लेषण कीजिए।

विश्व व्यापार संगठन, वर्ष 1995 मे स्थापित संगठन है, जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य विश्व व्यापार को पारदर्शी सुगम, सरल बनाना है।

विश्व व्यापार संगठन के समक्ष चुनौतियाँ

- वर्तमान मे विवाद समाधान बॉडी मे आवश्यक पेशेवर नही है (3 आवश्यक) जिससे संगठन का यह तंत्र सुप्त अवस्था मे है।
- साथ ही संगठन मे विकासशील व विकसित देशो के बीच गुटबाजी महत्ती हो गई, और अमेरिका जैसे देश संगठन की नीतियो से बाहर आ रहे है
- साथ ही वर्तमान मे बढ़ता संरक्षणवाद, संगठन की प्रभाविता

के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगाता है
जैसे व्यापार युद्ध का होना

- इसके अलावा देशो द्वारा विकृत गतिविधियो को अपनाना जैसे चीन द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन

- बौद्धिक संपदा अधिकारो को लेकर मुद्दे जैसे एवर ग्रीनिंग, (ग्लाइवेक कंपनी) अनिवार्य लायसेंसिंग, समानांतर आयात

- संगठन मे सुधारो को लेकर आपसी सहमती न होना व पीस क्लॉज का प्रभावी न होना व स्थायी समाधानो को लेकर निष्क्रियता

- इसके अलावा निवेश संबंधी मुद्दे जैसे भारत - USA के मध्य सोलर पेनलो को लेकर आदि।

उपरोक्त गतिविधियो ने संगठन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है

- संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन अप्रभावी हो रहे हैं
- साथ ही देश मे कोविड के दौरान व वर्तमान मे संरक्षणवाद बढ़ता जा रहा है।
- संगठन के निर्णयो की उपेक्षा हो रही है,
- साथ ही देश अब क्षेत्रीय समझौतो से मुद्दो को सुलझा रहे है

विश्व मे समावेशी व स्वतंत्र व्यापार गतिविधियो के लिए विश्व व्यापार संगठन आवश्यक है, और इसके लिए विवाद समाधान तंत्र मे पर्याप्त पेशेवरो की नियुक्ति व ऐच्छिक सदस्यों समय की जरूरत है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. BIMSTEC is indispensable for India's efforts in promoting regional cooperation and integration in the neighbourhood. Discuss. **(250 words) 15**
बिम्सटेक (BIMSTEC) पड़ोस में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में किए जाने वाले भारत के प्रयासों हेतु अपरिहार्य है। चर्चा कीजिए।

बिम्सटेक, दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशो का एक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1997 मे हुई।

भारत के पड़ोस मे क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा मे बिम्सटेक का महत्व ~

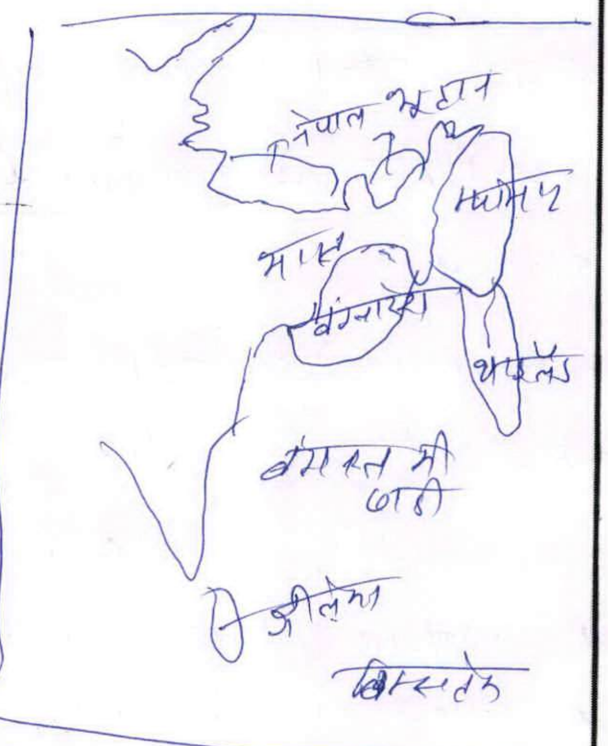

~~बिम्सटेक~~ किसी भी प्रकार के राजनीतिक कलह से मुक्त है, इसलिए एकीकरण की संभावना है (चीन, पाक नहीं)

साथ ही सार्क के निष्प्रभावी होने पर इस क्षेत्र मे एकीकरण व सहयोग के लिए यही एकमात्र

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

संगठन है।

- साथ ही बिम्सटेक भारत के दक्षिण पूर्व एशिया से प्रभाव को पैदा करता है
- इसके अलावा इन देशो मे बढते चीनी प्रभाव को कम करने के लिए बिम्सटेक एक प्रमुख संगठन है (नेपाल मे BRI आदि)
- साथ ही विभिन्न मुद्दो पर सहमति के लिए भी बिम्सटेक आवश्यक है, जैसे आर्थिक सहयोग व एकीकरण
- इसके अलावा क्षेत्र मे भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासो के लिए बिमसटेक का सहयोग आवश्यक है (जैसे बांग्लादेश, म्यांमार)
- साथ ही कालादान मल्टीमॉडल परियोजना, अन्य परियोजना के प्रभावी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

क्रियान्वयन के लिए बिम्सटेक की आवश्यकता है

- इसके अलावा सार्क लेवल BBIN, मोटर व्हीकल समझौता आदि में सहमती के लिए भी बिम्सटेक का सहयोग आवश्यक है।
- साथ ही इन क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण व हित पूरकता के लिए भी बिम्सटेक की आवश्यकता है।

उपरोक्त सहयोग के लिए भारत को प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता है, साथ ही गुजराल सिद्धांत, पड़ोसी देश पहले की नीति का क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है।